



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

मसाघारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

मई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 1990/ज्येष्ठ 30, 1912

No. 152] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 1990/JYAIKTHA 30, 1912

इस भाग में निम्नलिखित रूप से वीचा आता है जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

बाणिज्य मंत्रालय
(आयात व्यापार नियंत्रण)
सार्वजनिक सूचना सं. 30 आईटीसी (पी.एन.)/90-93
नई दिल्ली, 20 जून, 1990

विषय:—जापान सरकार द्वारा विस्तारित 1989-90 के
लिए 467.093 मिलियन येन (येन 467,093,000)
(ऋण सहायता) जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्व-
जनिक क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग शर्तें।

फाइल सं. आईपीसी/23(61)/90-93 से जारी:—
जापान सरकार द्वारा विस्तारित 1989-90 के लिए
467.093 मिलियन येन (येन 467,093,000) (ऋण
सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक
क्षेत्र द्वारा आयातों को शासित करने वाली शर्तें, जो इस सार्व-
जनिक सूचना के परिणाम में दी गई हैं, सूचना के लिए
अधिसूचित की जाती हैं।

ह. /—
तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रित

बाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 30
आईटीसी (पी.एन.)/90-93, दिनांक 20-6-1990
का परिशिष्ट

जापान सरकार द्वारा विस्तारित 1989-90 वर्ष के
लिए 467.093 मिलियन येन (येन 467,093,000)
(ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत
पब्लिक सैक्टर के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग शर्तें।

भाग—1 सामान्य शर्तें

1. (1) जापान सरकार द्वारा विस्तारित 467.093
मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता ओ.ई.सी.डी.
और विकासशील देशों के लिए खुली है। तबनुसार इस
अनुदान के अंतर्गत अधिप्राप्ति की जाने वाली वस्तुएं और
प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उद्दून
सभी देशों में अधिप्राप्ति की जा सकती है। ये देश इस
अनुदान के अंतर्गत पात्र स्ट्रो-1-देश होंगे। इस अनुदान के
अंतर्गत जो पात्र मद्दें आयात की जा सकती हैं उनकी सूची
अनुबन्ध-2 में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक शीष्क “1989-90 के निए (येन 467.093 मिलियन) जापानी अनुदान सहायता” होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत “एस/जेएन” होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण के लिए आयात लाइसेंस के अधिगति पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

1(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेणण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेणण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रांत नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय स्पष्टे में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक बैधता अवधि के नाथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की बैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंस-धारी को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी में संपर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर) अबर सचिव (जापान) आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। “पक्के आदेशों” का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रम आदेशों से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्तान्तरित हों। विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश और/या भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं हैं।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाने हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आधिदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि यूद्ध इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव

निरपेक्ष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत-नदान के लिए आधिकारी नियम नियमित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह नियम 31-3-1991 के बाद की न हो।

खण्ड-2 संभरण ठेके का समझौता करने ममव ध्यान में रखने जाने वाली विशेष बातें —

2(1)(क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या पात्र, डाकर या पौण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेंट या एक येनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय स्पष्टे में चुकाना चाहिए। भारतीय स्पष्टे या किसी अन्य मूद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत-बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्च वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए। पात्र भाड़े का इन्हें वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) अब आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंचेजी में होने चाहिए।

2(2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा ही जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तर्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

2(3) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देश का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और ममाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड-3 संभरक ठेकों में नियन्त्रित शर्त रूप में समाविष्ट होनी चाहिए।

3(1) 1989-90 के लिए येन 467.093 मिलियन की अनुदान सहायता में सम्बद्ध इस संविदा की व्यवस्था 13-12-1989 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है जो भारत सरकार के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगी।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस “भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/वी) के माध्यम से किया। जाएगा जो 1989-90 वें लिए जापान अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जनपथ भवन, जनपथ, बी विंग छठा तल, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और वस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहभत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3(4) उस मामले में, जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और वह भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोत परिवहन की व्यवस्था करने के लिए सहभत है और वह कि वह संबंधित माल की सुपुर्दी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचना देगा और कम-से-कम 6 सप्ताह पहले से भारतीय दूतावास टोकियो को नोटिस देगा जिससे पोत परिवहन की उचित व्यवस्था की जाए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए। अपवादस्वरूप मामलों में, यदि आयातक घाहे तो नोटिस की इस अवधि में कमी की जा सकती है। जापानी संभरक को आवश्यक व्यौरा देते हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद आयातक को केवल द्वारा सूचना भेजने के लिए भी सहभत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारत के दूतावास टोकियो को भेजनी चाहिए।

खण्ड-4 भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :—

(4)(1) जैसे कि आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाएं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विभिन्न हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियों या समुद्रपार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आवेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियों या उसकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-3 के प्रपत्र में “ए/वी” जारी करने के आवेदन को दो प्रतियों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों अवर सचिव, (जापान) आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय-वस्तु या उसकी कीमत में होने वाले अनिवार्य संशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए लागू होंगी।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज “ए/वी” जारी करने के लिए आवेदन-पत्र अन्य संबिंदित दस्तावेज सही पाए जाएं तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास टोकियो और भारत में जापान के राजदूतावास को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद सहायता और लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, जनपथ,

नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए अनुबंध-4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए “भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/वी)” जारी करेगा। ए/वी की प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियो आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएंगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/वी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास, टोकियो आयातक के भारत में बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इसकी प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

4(5) पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/वी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित अपने बैंकरों के माध्यम से संभरक को दस्तावेजों में निविष्ट धनराशि को रिलीज करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/वी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे भारत में आयातक के संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेवे को प्रभावित किए जिन्हा ही निर्धारित किए जाएं। लेकिन, सरकारी विभागों के मामले में, भारतीय दूतावास टोकियो बीओआई, टोकियो को बैंकिंग प्रभारी का भुगतान करेगा और फिर उसे सम्बद्ध विभाग के नामें डाला जाएगा।

खण्ड—5 रुपया जमा करने का उत्तरवायित्व :

5(1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज नियमावाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबंध-3 के रूप में उल्लिखित है) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सैट केवल इस बात को सुनिश्चित कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई रुपया (यू.एस.डालर) पौंड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है व्याज के खर्चे सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है व्याज के खर्चे सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हिसाब लगाकर व्याज सावंजनिक सूचना स. 31-आईटीसी (पीएन)/83, 10-8-83 और सं. ए 35-

आईटीसी (पीएन) /83, दिनांक 26-8-83 के अनुसार सरकारी लेख में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिनों प्रथम् जिस विन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेख में रूपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। वेक्षण सार्वजनिक सूचना यं. 103-आईटीसी(पीएन)/76, विनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी(पीएन)/74, दिनांक 31-5-1974 भुगतानों की येत यू.एस. डालर/पौष्ट धनराशि के बारबार रूपये की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-नियर्ति की सार्वजनिक सूचना सं. 113-आईटीसी(पीएन)/88-91, दिनांक 6-4-89 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जोकि मुख्य नियंत्रक, आयात-नियर्ति की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चय करने का उत्तर-दायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेख में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि असाधारण परिस्थितियों में सीमानुक्रमिक प्राधिकारियों से मूल पोत-परिवहन दस्तावेजों के बिना भाल का विवरण प्राप्त कर लेने पर धनराशि सरकारी लेख में शीघ्र जमा करा दी गई है। जिस लेख शीर्ष में उपर्युक्त रूपया जमा करना चाहिए वह है कि छिपोजिट एण्ड एडवान्सिज 8443-सिविल छिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परजेजिंग एटसट्रा एक्रांड-परजेज ग्राण्ट ऐड फार्म गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1989-90 (येत 467.093 मिलियन ग्रान्ट ऐड अरुण सहायता)। तथापि, सरकारी विभाग द्वारा कोई व्याज अदा नहीं किया जाता है।

5(2) उल्लिखित धनराशि चालान के दाहिने और कोड सं. 5130000000 दर्शते हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साथ में नकद जमा होनी चाहिए या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इस के उप-संगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डी कर्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (छिमाण्ड इफट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्रापक) को सार्वजनिक सूचना संख्या 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 और सार्वजनिक सूचना सं. 113-आईटीसी(पीएन)/88-91 दिनांक 6-4-89 में यथा निर्धारित सरकारी लेख में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बन्धित भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए चालान के विभिन्न कालभौं को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को

इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सम्पूर्ण सूचना निरपवाद रूप से भेज दी गई है: खजाना चालान में निम्नलिखित व्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

- (क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं. और विनांक।
- (ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निष्क्रिय किए जाने हैं।
- (ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।
- (घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना जाएगा।
- (ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(व्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेख में समतुल्य रूपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है लेकिन सरकारी विभागों द्वारा कोई व्याज देय नहीं है।)

उसके पश्चात् सी.ए. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का सन्दर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रूपया जमा करने का साक्षय देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी.ए. ए. एण्ड ए. की भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रूपये का निष्क्रिय बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अद्यायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतवादान दस्तावेजों की प्राप्ति के दस विनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी.ए. ए. एण्ड ए., वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में संबद्ध बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रूपया निषेधों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड—6 विविध शर्तें:—

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट:—

* * * आयातक को सम्भरक को अदा किए गए भुगतान की राशि और तिथि का पता करने के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। आयातक के अदाता द्वारा पोत परिवहन आवि दस्तावेजों की बाद में यादेरी से प्राप्ति को रूपया निष्क्रिय पर देय व्याज की आंशिक या पूरी धनराशि को माफ करने के लिए बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत कराये जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

6(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी जाने वाली शर्तें साक्षात् भुगतान के नियमन के अन्तर्गत अनुबंध-1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निपटाने की शर्तें छेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

6(4) भावी अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1989-90 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियंत्रणों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गयी शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-नियर्ति (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंधों की सूची :—

अनुबंध-1	पात्र स्रोत देशों की सूची
अनुबंध-2	पात्र पथ्य वस्तुओं की सूची
अनुबंध-3	भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र
अनुबंध-4	भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) का प्रपत्र।

**आयातकों पोतलदान और उसके मद्देन्द्र भुगतान और बकाया रह गई राशि से सम्बन्धित एक मासिक रिपोर्ट प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रण, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, 5 वीं मंजिल, सौ विंग, जनपथ नई दिल्ली 110001 को भेजनी चाहिए।

अनुबंध—1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) ओईसीडी देश

आस्ट्रेलिया
कनाडा
फिनलैंड

जर्मनी संघीय गणराज्य

आइसलैण्ड
जापान
दी नीदरलैंड
नार्वे
स्पेन
स्वीटजरलैंड
दि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड-स्टेट्स
बेलजियम
डेनमार्क
फ्रांस
यूनान
इटली
लगजमबर्ग
त्यूजीलैंड
पुर्तगाल
स्वीडन
तुर्की

(ख) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(ख-1) नान-ओ.पी.ई.सी. विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिश्र
मोरक्को
तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला
वर्षाण्डी
केप वड़ी द्वीप समूह
चाड
कांगो, दमोह गणराज्य (1)
इथोपिया
धाना

गुयाना
बोत्सवाना
केमेरून
केन्द्रीय अफ्रीकन गणतंत्र
कमोरो द्वीप समूह
इक्वटोरियल गाइना
जांबिया

सेंट हेलिना और डेम (2)
सौ टोम प्रिन्सीपि
आइरी कोस्ट

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश फरनेडों द्वीप समूह।

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित असैन्धन, टिस्टन डा इन एस्सेसिवल्स, नाइटिंगेल, गफा।

कैन्या	सेंट पियरी और मिल्युलोन
निसोधे	ट्रिनिडाड टावागो
लाइबेरिया	वेस्टइंडिज (बा.)एन.आई.ई.
मालागासी गणतंत्र	(क) संबंधित राज्य (1)
मलावी	(ख) आश्रित राज्य (2)
मारिटेनिया	4. दक्षिणी अमरीका
मारीणस	अजॉन्टीना
मोजाम्बिक	बोलिविया
नाइजर	ब्राजील
पुर्तगाल गिनी	चिली
रि-युनियन	कोलम्बिया
रोडेशिया	फालकलैंड द्वीप समूह
खाण्डा	फांसिसी गिनी
संनेगाल	गुयाना
सिचिलीज	पराग्वे
सियरा लिओन	पेरू
सोमालिया	सूरिनाम
सूडान	उरुग्वे
स्वीजीलैंड	5. मध्य पूर्वी एशिया
टेंरी अफासी और इस्सास	बहरीन
टोंगा	द्विजराह्ल
युगाण्डा	जोर्डन
तंजानिया गणतंत्र संघ	लेबनान
अपर बोल्टा	ओमन
जायरे गणतंत्र	सिरियाई अरब गणतंत्र
जांबिया	यूनाइटेड अरब गणतंत्र (3)
3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय	यमन अरब गणतंत्र
बेहूमस	यमन जनवादी डी.आर (4)
बारबाडोज	6. दक्षिणी एशिया
बेलाइज	अफगानिस्तान
वरमूडा	बांगला देश
कोस्टारिक	भूटान
क्यूबा	बर्मा
डोमिनिकल गणतंत्र	मालदीप
एल साल्वाडोर	नेपाल
गवाडिलाथप	पाकिस्तान
ग्वाटेमाला	श्रीलंका
हैंदी	
होण्डरस	
जमैका	
मार्टिनिक्यू	
नीदरलैंड एटिलीज	
मैक्रिस्को	
निकारागूआ	
पनामा	
(3) ऐन समूह, अरबा, बोनाहे, क्यारा कास्त्रो, सहा, सेंट युस्टासिट, सेंट मार्टिन (दक्षिणी भाग)।	(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुआ, टोमिनिका, प्रेनेडा, सेंट कीह्स (सेंट करिस्टोके), नेविस अंगुइला, सेंट लुसिया और सेंट विसेकट।
	(2) मेन आईलैंड, मोन्टेसे रेंट, येमान, तुर्की और काइकोस और अंटिलिया वरजिन द्वीप समूह।
	(3) आई जुमन, दुबई, फजाहरह, रास अल खेमाह और जाह
	और उम्मल बचेवन।
	(4) घदन और विभिन्न सत्तन और अमीरात सहित।

7. सुरुर पूर्व एशिया
बृनेई
हांगकांग
हेमर गणतंत्र
लाओस का कोम्हिया गणतंत्र
मकाओ
मलेशिया
फिलीपाइन

8. कोक आइसलैण्ड
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैंड
तिभाई
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया
कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल गिल्वर्ट और इलाइम द्वीप
फांसिसी पोलिनेशिया (5)
नारङ्ग
न्यू कोलोडोनिया
हिपु
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य यू.एम.) (6)
पापओ न्यू गिनी
सोलामन द्वीप समूह (हि.)
टोगो
न्यूकेफिसैसे (ब्र. और प्र.)
वालिस और कतुना
पश्चिम भारतीय

9. यूरोप
साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
युगोस्लाविया

(5) मोमायटी, आईसलैण्ड समूह (नाहिसी सहित) को शामिल करने हुए अस्टल द्वीप समूह, दुआमोट, जांवियर ग्रुप और मार्कोसल द्वीप समूह ।

(6) केंसिफिक द्वीप समूह का द्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और पैरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

खण्ड-2 श्रो. पी. ई. भी. के सदस्य या मह्योगी देश
श्रीलंका
वोलिबिया
लीबिया और गगतंत्र
गेवान
नाइजीरिया
उच्चवैष्णोर
ब्रेल्यूएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
मऊदी अरब
उन्डोनेशिया
आबू धाबी

अनुबन्ध 2

पात्र पाप्य वस्तुओं की सूची

1. रोलज
2. विशेष इस्पात और मिथ-धातु इस्पात महिन इस्पात
3. टूकों और ट्रेक्टरों हूल्के व्यापारिक ब्हील और टू ब्हील के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे ।
4. रसायन
5. जापान अनुदान परियोजना और भारत जपान संयुक्त उधम के लिए फालतू पुर्जे संघटक और कच्चा माल ।
6. विजली के कुकों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे ।
7. मशीनरी, संघटक संयोजन, अनिरिक्षा पुर्जे और कच्चा माल ।
8. लघु उद्योग थेस्ट के लिए मशीनरी और उपस्कर ।
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए मशीनरी, उपस्कर और अनिरिक्षा पुर्जे ।
10. उर्वस्क और ऐमी अन्य मर्दे, जिन पर ग्राम में सहमति हो ।

अनुबन्ध-3

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र”

में,
मेवा में

महायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक,
विस मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
पृ. सी. ओ., बैंक विलिंग,
प्रथम मंजिल, पालियामेट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

विषय:- 1989-90 के लिए येन 467.093 मिलियन जापानी रुण अनुदान सहायता येन के अधीन जापान में प्राप्ति ।

गहोदय,

अनुबन्ध-4

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से जो कि आयात के संबंध में है संबद्ध संभरक के नाम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आपको निम्नलिखित और प्रस्तुत करते हैं :—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात साइसेंस की सं., दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके क्या यह सीधे क्य या श्रौप-चारिक खुले अंतरीष्टीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण महित यह संकेत होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण।
- (ङ.) माल का उद्गम देश
- (च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)
- (छ) यदि कोई हो तो भारतीय भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि।
- (ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) संभरकों के साथ की गयी संविदा की संख्या और दिनांक
- (ञ) संभरक का नाम और पता
- (ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगी।
- (ठ) सुपुर्देगी की पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।
- (ঃ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करने समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए।
- (ঁ) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट की जाए।
- (ং) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।
- (ঃ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई है। यदि हाँ, तो ऐसी संविदा का दिनांक और मूल्य।
- (ঁ) वह भारतीय पत्तन जहाँ उपकरण/माल का पोतलदान किया जाना है।

भवदीय,
हस्ताक्षर

सं.

भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय:—येन 467.093 मिलियन के लिए जापान अर्हण अनुदान सहायता के अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के पास दिनांक—— को किए गए करार के नियम और शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा मैसर्जे को (परिणिष्ठ में दिए गए और के प्राप्तार)

..... येन तक की धनराशि को भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाए है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए.सी.पी.) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिणिष्ठ में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करने के बाद, आपको (आयातक के बैंकर का नाम और पता) को सभी मूल पोत परिवहन दस्तावेजों (परकार्य) और उसके साथ-साथ दस्तावेजों के अतिरिक्त पूरे सेट और यदि कोई तत्काल भुगतान किया गया हो तो उसके सहित संभरक को किए गए भुगतान के अर्हण बीजक को एक प्रति भेजनी चाहिए।

5. आयातक द्वारा दस्तावेजों के भेजने आदि के लिए भाड़ों महित प्रदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े भारतीय दूतावास टोकियो आयातक बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तथापि, भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा ई. ओ. आई. को सरकारी विभागों से सम्बद्ध बैंकिंग भाड़ों का भुगतान किया जाएगा और संविधित विभाग के नामें डाला जाएगा।

6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लक्षान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा।

9. कृपया संविदा से संबंधित सभी पत्राचार में और भुगतान दस्तावेज वाले बीजाक में भी भुगतान के लिए इस प्राधिकार पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या को छोट करें।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति प्रेषित है:—

1. आयातक को उनके पत्र सं. दिनांक के सदर्भ में

(1) यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र येन अनुदान के अधीन आयातों को नियंत्रित करने वाली संगठ लाइसेंसिंग शर्तों के अधीन जारी किया जाता है। लाइसेंसिंग शर्तों और संबद्ध सार्वजनिक सूचनाएं और प्रादेशी आदि का अवलोकन किया जाए और संबंधित आयात/विदेशी भुगतान के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों 1/4 येन यू.एस.डालर/पौंड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के रूपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन) 76, दिनांक 17-1-76 ऐसी सार्वजनिक सूचना को समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की नियंत्रित परिवर्तन की मिथित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए मार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन) /83, दिनांक 10-8-83 और 35-आई टी सी (पी एन) /83, दिनांक 26-8-83 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि भी जिसको विदेशी संभरक का भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निश्चेष किया जाता है।

1620 GI-90—2

(इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसको गूचना दी जाएगी)। यह मुनिश्वित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है तथापि, सरकारी विभागों द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है।

3. येन धनराशियां चालान के दाहिने ओर कोड सं. 5130000009 दर्शते हुए या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आवेशिती और आवाता के नाम में और उसको देय वर्गीय हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 113-आई टी सी (पी एन)/88-91, दिनांक 6-4-89 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की पर्ती की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह “के डिपोजिट्स एण्ड वे डिपोजिट्स जिन पर ब्याज नहीं है, एडवांसिंज 8443 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परवेजिस एटमैट्स परवेजिस अण्डर ग्रांड एड फाम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1989-90 (येन 467.093 मिलियन ग्रांट एंड डेबिट रिलीज)।

4. जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा में प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अप्रेयण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
जनपथ भवन, बी विंग, 5वीं मंजिल,
जनपथ, नई दिल्ली-110001

5. जिस मामले में तुल्य रुपया समय-समय पर जारी की गई सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित दर्जी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जना किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्याया इस विभाग को भेजना चाहिए।

6. समद्वयार संभरक के बैंकर के खातों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्च और बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्च इंशियन बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

7 विदेशी युद्ध में ग्राधिकृत व्यापारी के हैप में बैंक के कर्तव्य और जिम्मेवालियां, भारतीय रिजर्व बैंक के विधिवाली ए. डी. परिवर्तनों में निर्धारित हैं। इस संबंध में विशेष संदर्भ ए. डी. परिवर्तन सं. 22 दिनांक 18-6-77 को दिया जाता है।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अबर सचिव (टी. ए.) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 30 ITC (PN) 90-93

New Delhi, the 20th June, 1990

Subject.—Licensing Conditions in respect of Public Sector imports under Japanese grant aid of Yen 467,093 Million (Y 467,093,000) Debt-relief) for 1989-90 extended by the Govt. of Japan.

F. No. IPC/23(61)/90-93.—The terms and conditions governing Public Sector imports under Japanese grant aid of Yen 467,093 million (Y 467,093,000) Debt-relief) for 1989-90 extended by the Govt. of Japan, as given in Appendix to this public notice are notified for information.

TEJENDRA KHANNA,
Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 30 ITC (PN) 90-93 DATED 20-6-1990

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER JAPANESE GRANT AID OF YEN 467,093 MILLION (Y 467,093,000) (DEBT RELIEF) FOR 1989-90 EXTENDED BY THE GOVERNMENT OF JAPAN

Section I—General Conditions :

I. (i) The Japanese Grant Aid of Yen 467,093 million extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I. (ii) The licence will bear the superscription "Yen 467,093 Million Japanese Grant Aid for 1989-90. The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I. (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I. (iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity period of 12 months. For extension of the validity period of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I. (v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (Jap), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract only signed by both the Indian importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I. (vi) The condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why orders could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit by the licensing authorities who may grant further extension upto a maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of the import licence, such proposals will inevitably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1991.

Section II.—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract.

II. (i) (a) The C&E value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one cent or one penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II. (ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II. (iii) Eligibility of Supplier.

The supplier shall be a national of the eligible source countries or a judicial person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 13-12-89 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid—of Yen 463.093 Million for 1989-90 "and will be subject to the approval of Government of India".

III (ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Janpath Bhavan, 'B' Wing, 6th Floor, Janpath, New Delhi-110001 in favour of the Bank India, Tokyo under the Japanese Grant for 1989-90.

III (iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III (iv) Where suppliers are located in Japan they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV Contract Approval by Govt. of India.

IV (i) As soon as the orders are finalised, the licensee should forward to the Under Secretary (Jap) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the Overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier of their photo copies complete in all respects with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the "request for issue of A/P" in the format Annex. III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV (iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Janpath, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of the receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV (v) The foreign supplier shall, after effecting shipment, present through his banker the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents

are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittance to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account. However, in case of Govt. Depts., the banking charges are payable to B.O.I. Tokyo by the Embassy of India, Tokyo and then debited to the Depts. concerned.

Section V Responsibility for rupee deposit.

V (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (e) in Annexure-III who should release the negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen|USS Pound sterling payments made to the supplier along with interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 12 percent per annum for the first thirty days and at 18 percent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83 and No. 35-ITC(PN)|83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen|USS £ Payment will be prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 113-ITC(PN)|88-91 of 6-4-1989 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any changes in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Govt. account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. The Head of Account to which the above rupee deposit should be credited is "K-Deposits and Advances 8443 Civil Deposite-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1989-90 (Yen 467.093 Million Grant Aid-Debt-Relief). However, no interest is payable by Govt. Deptt.

V (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 513000000 on the right hand corner of the challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawee) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 and No. 113-ITC(PN)|88-91 dated 6-4-89.

V (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of Service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various

columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that complete information is invariably be furnished.

The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account). However, no interest is payable by Govt. Depts.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note.—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

SECTION VI.—Miscellaneous provisions

VI (i) Reports on the utilisation of the import licence.

**The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the foreign supplier. Late or delayed receipt of shipping documents etc. by the importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

VI (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI (iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Govt. of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all delegations under the Grant Aid for 1989-90 from Japan.

VI (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI (vi) List of Annexures

Annexure-I—List of eligible source countries.

Annexure-II—List of eligible commodities.

Annexure-III—Form of request for issue of Authorisation to pay (A/P).

Annexure-IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

**The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Vth Floor, 'B' Wing, Janpath, New Delhi-110001.

ANNEXURE-I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. OECD Countries

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
the United Kingdom and
the United States.

B. Developing Countries and Territories

(b) Non-OPEC Developing Countries

I. Africa, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II. Africa, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Camaroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's
Republic of
Dahomey (1)
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Libaria
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guineas
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and Dep (1).
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terror, Afars and
Isses
Tago
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. America, North and Cent

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tabago
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (2).
(b) Depend (3)

(1) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inacessibles, Nightingale, Gaugh.
 (2) Main islands. Aruba, Fonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, St. Martin Southern Part.
 (1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristeph), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (4)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D. R. (5).

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldives
Nepal
Burma
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Borneo
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Vietnam, Rep. of
Vietnam, Dem. Rep.

VII. Cock Island

Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (6)
Nauru
New Caledonia

(2) Main islands : Montserrat, Gayman, Turks and Caicos, and British, Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaiman, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (Including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

New B Hebrics (Br. and Fr.)
 Niue
 Pacific Islands (US) (6)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands (Br.)
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa

IX. EUROPE

Cyrus
 Gibraltar
 Greece
 Malta
 Spain
 Turkey
 Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria
 Bolivia
 Libyan Arab Republic
 Gabon
 Nigeria
 Ecuador
 Venezuela
 Iran
 Iraq
 Kuwait
 Qatar
 Saudi Arabia
 Abu Dhabi
 Indonesia

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (Except Guam).

ANNEXURE—III**"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION
TO PAY"**

NO.

To,

The Controller of Aid Accounts & Audit,
 Ministry of Finance,
 Department of Economic Affairs,
 UCO Bank Building, 1st Floor,
 Parliament Street,
 New Delhi-110001.

Subject : Import under the Japanese Debt-Relief Aid of Yen
 467.093 million for 1989-90.

Sir,

In connection with the import of _____ from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen). If any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Suppliers.
- (j) Name and address of the Supplier.
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of delivery.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo, (inc) indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (Indicate if transhipment/ part shipment permitted or not permitted)
- (o) Name and address of the Importer's Bank in India.
- (p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.
- (q) Indian port to which the equipment/materials are to be shipped.

Signature

ANNEXURE-IV

Copy forwarded to :—

No. _____

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Sub :- Import under Japanese Debt-Relief Grant Aid of Yen
467.093 Million — Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated _____ entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen _____ to M/s. _____ (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of the authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign supplier, you should send to _____ (Name & address of importers' Banker) all the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Toko/Importers' Bank. However, the banking charges in respect of Govt. Deptt. will be payable to Bank of India, Tokyo by the Embassy of India, Tokyo and debited to the Deptts. concerned.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's Bank.

7. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from the Ministry.

8. The A/P will remain valid upto _____

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully,
Accounts Officer

1. Importer _____

with reference to their letter No. _____
dated _____

2. Importers' Banker.....

(i) This authorisation to pay is issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen grants. the licensing conditions and connected Public Notices or orders etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen 1/4 US \$/£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo, Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notice as may be issued from time to time. Interest @ 12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-1983 and No. 35 /ITC/PN/89 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be notified if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance. However, no interest is payable by Govt. Deptts.

(iii) These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 513000009 on the right hand corner of the challan or the S.B.I. Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 113-ITC(PN)/88-91 dated 6-4-1989 and 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits (4) & Deposits not having interest Advance 8443 CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1989-90 (Yen 467.093 Million Grant Aid-debt Relief).

(iv) One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Janpath Bhawan, 'B' Wing, 5th Floor, Janpath, New Delhi-110001.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notices issued from time to time, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest at the rate prescribed and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

(vii) The Banks' duties and responsibilities as authorised Dealer in Foreign Exchange are prescribed in various A.D. circulars of the Reserve Bank of India. Specific reference in this regard is invited to A.D. Circular No. 22, dated 18-6-1977.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (Jap.), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001 with reference to I.D. No. /Jap, dated

(Accounts Officer)